[Shri P. A. Sangma]

there is a lot of demand for raising the existing limit of eligibility for payment of bonus from Rs. 2500 p.m. to Rs. 3500 p.m. to which Mr. Pachouri referred.

AN HON. MEMBER: Mr. Puglia.

SHRI P. A. SANGMA: I am sorry, Mr. Puglia. Sir, I would not be able to commit anything on this because it mainly concerns the Ministry of Finance. Now, I can only assure the House as a Labour Ministry we will take up the issue with the Finance Ministry. That much I can say. (*Interruptions*)...That is why I am saying we will have to take it up with the Ministry of Finance. We will take it up with the Ministry of Finance. Without that I cannot do anything. As far as secret ballot is concerned about which Dr. Reddy has spoken, the Industrial Relations Bill which was introduced in this House was withdrawn and where the question of secret ballot or check-off system was there, it was referred to the Ramanujam Committee. I think, the House knows about it and it was referred to the Ramanujam Committee again for re-examining the whole thing. The Ramanujam Committee has submitted its Report and that Report also has to go to the Indian Labour Conference and it is the Indian Labour Conference which will discuss this. So, I am not able to say the position as of now because in the beginning itself I said that the Labour Ministry is such a Ministry that it has to work within the parameters of a tripartite mechanism.

SHRI NARESH PUGLIA: He has not replied to the question of provident fund of bidi workers.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please now it is over. He will look into it.

SHRI NARESH PUGLIA: He must reply about bidi workers' provident fund. I have asked a specific qu tion.

THE VICE-CHAIRMAN (SH BHASKAR ANNAJI MASODKA You cannot force him. Now, will proceed to the Appropriat (No. 4) Bill, 1991.

THE APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 1991.

THE MINISTER OF STATE THE MINISTRY OF FINA (SHRI SHANTARAM POTDUKH Sir, I beg to move:

"That the Bill to authorise p ment appropriation of certain su from and out of the Consolida Fund of India for the services the financial year 1991-92, as pa ed by the Lok Sabha, be tak into consideration."

The Bill provides for withdraw out of the Consolidated Fund of In of the amounts required to meet expenditure for the year 1991- charged on the Fund as well as Grants voted by the Lok Sabha.

Gross disbursement of R 2,26,211.53 crores are provided in t Bill. After setting off the recoveri receipts taken in reduction of expe diture and transactions in the natu of accounting adjustments, the n provisions aggregate to Rs. 1,13 crores. Of this, an amount of R 33,725 crores is for Central Plan a Central assistance for State and Uni Territory Plans. The provision defence expenditure is Rs. 16,3 crores, for interest payment Rs. 27,4 crores, for subsidies Rs. 10,395 cror including Rs. 1,500 crores for pr viding debt relief to farmers, a for pensions Rs. 2,298 crores. Othe non-Plan grants and loans to Sta and Union Territory Governmen account for Rs. 9,547 crores, non-Pl capital outlay Rs. 1,176 crores, no Plan loans to public enterprises Rs

Rs. 632 crores, and grants and loans to foreign Governments Rs. 1,395 crores. The balance of Rs. 10,454 crores is for other expenditure including expenditure of Union Territories without Legislature.

The amounts provided in the Bill are inclusive of the sums already authorised in Appropriation (Vote-on-Account) No. 2 Act, 1991.

The House has already had a general debate on Budget. I would not, therefore, enumerate the details of the budget provisions but shall try to deal with the points that may be made by the hon. Members in the course of discussion.

Sir, I move.

The question was proposed.

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 1991, जिसमें भारत की संचित निधि में से 22 खरब, 62 अरब, 11 करोड़, 35 लाख रुपयों का दिया जाना निहित है, वह वित्त राज्य मंत्री ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मैंने शुरू में ही आपको यह कहा था कि डा० मनमोहन सिंह जी रहते तो शायद कुछ और अधिक जोरदार ढंग से यह सदन उनके साथ अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकता था। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि जिस ढंग से... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): But the represents the Minister.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: There is no difference. But I am making my own points.

कि मनमोहन सिंह जी जिस तरह से वित्त मंत्री के रूप में आए और जेट की तरह से चले और जिस तरह से उन्होंने घोषणाएं की और जिस तरह से उन्होंने दिशाएं देने की कोशिश की, कुछ ही दिनों में ऐसा लगता है कि जेट की चाल से चल कर वह बामुहूत के अनुसार अब नीचे उतर रहे हैं। देश की जो आर्थिक स्थिति है उस संबंध में मैं कहना चाहता था। उपसभाध्यक्ष जी, इस सदन के लिए बड़े दुख की बात है कि एक तो आप जानते हैं कि बहुत कम विषयों पर इस सदन में चर्चाएं होती हैं, कहा जाता है इसको बजट सत्र, लेकिन बजट नाम की चीजों पर सब से कम यह सदन अपना समय देता है, लोक सभा में कुछ अधिक चर्चा होती है। इस सदन में जबकि हम लोगों ने बहुत काट-छांट करके यह सोचा कि चार विभागों के ऊपर या चार मंत्रालयों के ऊपर इस सदन में चर्चाएं होंगी, लेकिन चार पर भी चर्चाएं नहीं हो सकीं। इन्फर्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग के ऊपर और लेबर के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, कामर्स के ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर चर्चा होनी थी, डिफेंस और कामर्स बहुत बड़े सब्जेक्ट थे, उसको भी काट कर आपने टेक्सटाइल कर दिया। मैं सब से पहले तो इस माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा, हमारे पार्लियामेंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर यहां पर थे, कहीं गायब हो गए, क्या सदन चलाने की प्रक्रिया यही होती है कि सदस्यों को अंधकार में रख कर सदन को चलाओ सदन के सामने जब बजट सत्र है तो बजट की सारी चीजें आनी चाहिए थीं, सभी डिमांड्ज पर चर्चा होनी चाहिए थी। इसलिए दुख के साथ कहते हुए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सदन की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो चीजें आई थीं कि चार विषयों पर विचार होगा, डिफेंस पर, कामर्स पर, लेबर पर, इन्फर्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग पर, उन चारों विषयों पर चर्चा होनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने हमारे सामने यह विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया है और भारत की संचित निधि में से जिस राशि की मांग की है वह राशि तो सरकार यह मान कर चलती है कि मिल ही जाएगी और इतनी बड़ी राशि जिसका

[श्री शंकर दयाल सिंह]

जिक्र इस एप्रोप्रिएशन बिल में है, इस राशि को पढ़ने से ही लगता है कि बहुत बड़े विशाल देश और बहुत बड़े समृद्ध देश की ओर से यह एप्रोप्रिएशन बिल प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि खरब, अरब और करोड़ की संख्या अपने आप में एक भयानक संख्या है जो किसी को भी आतंकित कर देने के लिए बहुत बड़ी चीज है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज देश की स्थिति क्या है? खरबों और अरबों का तो जिक्र हम कागज में कर लेते हैं, विधेयक पास कर लेते हैं, मंत्री महोदय के मुंह से सुन लेते हैं, कागजों में पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर लोगों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, रहने के लिए उनके पास मकान नहीं है, जीवन जीने के लिए अगर उनके पास सुरक्षा नहीं है, बच्चों को ठीक से दवा-दारू कराने के लिए इलाज का साधन नहीं है तो मैं समझता हूं कि उस गरीबी की ओर सरकार ने जरा भी ध्यान नहीं दिया उपसभाध्यक्ष जी, मैं क्यों इन बातों का जिक्र आपसे करना चाहता हूं, वह भी मैं खास तौर से कर दूं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह आज हमारे सामने विनियोग विधेयक इतना बड़ा है, तो आज से दस, बारह, पन्द्रह साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत बड़ा फर्क आ गया है, इसीलिए इस विनियोग विधेयक को, जो आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया है द एप्रोप्रिएशन (नंबर 4) बिल, 1991, उसको अगर ठीक ढंग से देश को सामने रखकर लाना चाहते तो शायद देश का नक्शा कुछ और होता।

महोदय, 6 चीजों की ओर ध्यान देने की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। एक तो मूल्य वृद्धि है जिसके कि नीचे लोग तड़फ रहे हैं, उसकी ओर। महोदय, मैं महंगाई के बारे में बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं समझता हूं। इसके लिए जो आर्थिक सर्वेक्षण केन्द्रीय सरकार ने इस बार जुलाई में प्रस्तुत किया है, उसको देख लीजिए और आज के अखबारों की ओर वित्त राज्य मंत्री और सभी का ध्यान गया होगा कि आज क्या स्थिति है दो महीने के अंदर मूल्य वृद्धि 15 प्रतिशत से भी आगे बढ़ गयी है। दो महीने पूर्व जब आपने आर्थिक समीक्षा हमारे सामने प्रस्तुत की थी और आज जो हमारे सामने एप्रोप्रिएशन बिल ला रहे हैं, इन दो महीने के अंदर 15 प्रतिशत मूल्य वृद्धि हो गयी है।

महोदय, दूसरी तरफ सरकार में जो फिजूलखर्ची है उसको कम करने की दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है क्योंकि फिजूलखर्ची अगर बढ़ती गयी तो आप किसी तरह से भी आर्थिक संतुलन नहीं ला सकते।

महोदय, तीसरी बात मैं भ्रष्टाचार के संबंध में कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष जी, इसका जिक्र मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि हमारे जो बड़े-बड़े सार्वजनिक उपक्रम हैं या सरकार के बड़े-बड़े विभाग हैं या जो सरकार की बड़ी-बड़ी स्कीम्स हैं, जिनमें कि आप अरबों-खरबों रुपया खर्च करते हैं, उनका उपयोग कहां होता है उसकी उपयोगिता के लिए आपको भ्रष्टाचार से लड़ना पड़ेगा। उसके बारे में सरकार की ओर से एक भी शब्द ईमानदारी से नहीं कहा गया है। जो सबसे बड़ी चीज है वह है कि, अवमूल्यन की दर क्या है? जिस समय यह सरकार आयी थीं तो लोगों ने आशाभरी निगाहों से इसकी ओर देखा था, लेकिन एक सप्ताह के अंदर दो-दो बार इस सरकार ने रुपये का अवमूल्यन किया है। यह क्यों कहकर किया है? कहा गया कि आर्थिक दशा को सुधारने के लिए आर्थिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए इस अवमूल्यन के सिवाय और कोई चारा नहीं है। आर्थिक दृष्टि से स्वास्थ्य सुधारने के लिए अवमूल्यन किया मैं आज इसीलिए डा० मनमोहन सिंह जी को खोज रहा था कि आपने जिस आर्थिक स्वास्थ्य को सुधारने की बात कही थी, उसमें किस तरह का सुधार हुआ है, यह मैं उनके मुंह से सुनना

चाहता था। यह मैं इसलिए भी जानना चाहता था क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो मनिफेस्टो दिया गया था, उस में साफ शब्दों में लिखा गया है कि एक सौ दिनों के अंदर हम कीमतें को वहीं लाकर खड़ा करेंगे जहां पर कि पिछले दो साल पहले कीमतों का स्तर था। उसमें कहा था कि हम कीमतें बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन सौ दिनों के अंदर कीमतें किस तेजी से बढ़ी हैं कि इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा यह बताने के लिए आज का अखबार काफी है। इसमें जाकर मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। भारत सरकार की ओर से ही मुद्रास्फीति के बारे में और मूल्य वृद्धि के बारे में यह जो डाक्युमेंट दिया है सभी मेंबर्स को, यही इसकी कहानी कह रहा है। उपाध्यक्ष जी, मैं केवल इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 29-6-91 को बिंदु-प्रतिबिंदु हर चीज के बारे में सारी बातें कही गयी थीं, लेकिन 13 हफ्तों के दौरान मूल्य सूचकांक के अनुसार कीमतों में संचयी वृद्धि 2.4 प्रतिशत की हुई। यह बहुत खतरनाक स्थिति है। अगर इसी तरह से हम आगे बढ़ते गए तो स्थिति खतरनाक हो जाएगी।

महोदय, आप जानते हैं कि श्रद्धेय और स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बारे में जब भी बातें हुई हैं, हम लोगों ने राजीव जी के प्रति बहुत श्रद्धा व्यक्त की है। अगर यह सरकार उनके प्रति वास्तविक रूप में श्रद्धा व्यक्त करना चाहती थी तो उन्होंने जो कहा था कि एक सौ दिनों के अंदर हम कीमतों पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे, उसको कर दिखलाते तो देश को संतोष होता और उनके प्रति भी वह बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होती।

उपसभाध्यक्ष जी इसके बाद सरकार कौनसा बड़ा काम करने जा रही है? इस देश को कर्ज में डुबाकर हम लुभावने सपने दिखा रहे हैं लोगों को। आज कर्ज की स्थिति क्या है? सन् 1972-75 के बीच हमारे देश पर 6 हजार करोड़ डालर का कर्ज था। सन् 1972-73 के बीच छह हजार करोड़ डालर का कर्ज था। उस समय डालर की कीमत पांच या छह रुपए थी और आज डालर की कीमत पच्चीस से तीस रुपए के बीच हो गई है। रोज फलक्चुएशन उसका होता रहता है। इसलिए डालर अगर रुपए में करके देखें तो आज इस देश पर डेढ़ लाख करोड़ रुपए का कर्ज है।

उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार वित्त मंत्री कह रहे हैं कि यह कर्ज इसलिए लिया गया है कि इससे देश का स्वास्थ्य ठीक किया जाएगा। लेकिन, जहां कहीं भी कर्ज लेकर स्वास्थ्य ठीक करने की बात सोची गई है, उनका हाल, हश्र क्या हुआ है? यह अफ्रीकन देशों में जाकर देखिए या लेटिन अमरीका के देशों में जाकर देखिए। कर्ज में डूब गए हैं और उसी कर्ज को लेकर आप शान-शौकत की जिंदगी बिताने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं शान-शौकत की जिंदगी बिताने की बात कह रहा हूं तो कोई लच्छेदार भाषण के रूप में ही नहीं कह रहा हूं। आज हमारे सामने जो एप्रोप्रिएशन बिल है, उसी के आधार पर कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जरा इसको देखिए कि दिल्ली पर कितने खर्च की सीमा रखी है? दिल्ली के लिए कितने पैसे का प्रावधान किया है? दिल्ली आपकी राजधानी है। यहां चकाचौंध रहती है, सारे साधन उपलब्ध हैं, पांच सितारा संस्कृति है। पाश्चात्य बड़े से बड़े देश की राजधानी से यह टक्कर ले सकती है। यह कृषि प्रधान देश है। रोज हम इसकी चर्चा करते हैं और रोज किसानों, गांवों की दुहाई देते हैं। आपने दिल्ली के लिए तो 10 अरब 98 करोड़ 99 लाख रुपए का प्रावधान रखा है, लेकिन पूरे देश के वेटरिसोर्सेज के लिए केवल 3 अरब 38 करोड़ 92 लाख का प्रावधान रखा है।

उपाध्यक्ष जी, ऐसी स्थिति में हम क्या मानें? इस सरकार की नीयत गरीबों की ओर नहीं बल्कि यह अमीरों को और अमीर करना चाहती है और इसके लिए वह विदेश से कर्ज ले रही है। विदेश से कर्ज लेने के लिए उनकी शर्तों को मान रही है। आप डिवेल्युएशन कर रहे हैं, अवमूल्यन कर रहे हैं। जिस डालर की

[श्री शंकर दयाल सिंह]

कीमत छह महीना पहले आप 18 रुपए देते थे, आज उसकी कीमत 26 रुपए आप अदा कर रहे हैं। आप किस तरह कर्जा अदा करेंगे ? आप कर्ज में डूब जाएंगे। मूल तो मूल उसका सूद देते-देते यह देश बिक जाएगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत ही नम्र निवेदन के साथ यह कहना चाहता हूं कि सरकार सोचे इस चीज को। आपने मुद्रास्फीति 12.20 प्रतिशत तेरह हफ्ते में करके रखी है। रुपए की क्रय शक्ति को 467 पर ले जाकर हम आज दुनिया में कहां खड़े है आज दुनिया में हमारी स्थिति या तो भिखमांगे की है या हमारी स्थिति कर्जदार की है हमारी इज्जत कहां रह जाती है ?

उपाध्यक्ष महोदय, हमने अपने साधनों को ऊपर उठाने का नहीं सोचा है। आज सवेरे एक प्रश्न उपस्थित हुआ था, आपको याद होगा, गैस के बारे में एक सवाल यहां पूछा गया था। हम गैस का आयात करते हैं, जबकि हमारे यहां गैस का विपुल भंडार है। हम जानते हैं कि पेट्रोलियम में हमारी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। लेकिन, गैस का हमारे यहां त्रिपुरा में विशाल भंडार है। दुनिया के किसी भी देश में अगर उतना विशाल भंडार हो तो वह देश समृद्ध हो जाएगा। हम अपने विशाल भंडार से निकाल कर देश में नहीं पहुंचाते हैं बल्कि दूसरी ओर हम विदेशी मुद्रा देकर बाहर से ले आते हैं। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से जो कहना चाहता हूं, वह यह कि सबसे पहले आप अपनी आधार नीति तैयार कर लें कि आप कृषि की ओर जाना चाहते हैं या उद्योग की ओर जाना चाहते हैं या आप चकाचौंध की ओर जाना चाहते हैं ? अगर आप कृषि की ओर जाना चाहते हैं तो आप वह विश्वास मानो कि यह इस देश का किसान ही है, जो कि इस देश की आबरू को सुरक्षित रखे हुए है और समृद्धि को वह आपके सामने रख रहा है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में कृषि के उत्पादन का जो भी लक्ष्य रखा गया, यहां के किसान ने मर के, खप के उस उत्पादन-लक्ष्य को आगे बढ़ाया लेकिन उद्योग में आपने जो लक्ष्य रखा उस लक्ष्य की आप की पूर्ति नहीं हुई। सातवीं पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य हमारा 4.0 प्रतिशत का था, लेकिन यहां के किसानों ने 4.1 प्रतिशत पैदावार करके अपनी शक्ति और मेहनत का परिचय दिया। दूसरी ओर हमने किसानों को क्या दिया, जरा यह भी सोचिए बहुत गंभीरता से क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है? एक ओर किसानों ने, जो लक्ष्य आपने रखा उससे आगे बढ़कर पैदावार की और दूसरी ओर आपने किसान पर उर्वरक का दाम इस तरह से घोप दिया कि अब कोई किसान खाद खरीदकर खेत में पहुंचा नहीं सकता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस समय सोवियत संघ से यह जलजला हुआ मैं सोवियत संघ में था और सोवियत संघ को मैंने नजदीक से समझने की कोशिश की। आखिर सोवियत संघ कहां फेल कर गया? आर्थिक रूप से फेल होने पर आज दुनिया की इतनी बड़ी महा-शक्ति, इतना बड़ा देश दुनिया के सामने प्रश्न-चिन्ह बनकर खड़ा है। इसलिए कि उसने वहां कृषि को गौण रखा और उद्योग को प्रमुख रखा। अगर 60 प्रतिशत या 63 प्रतिशत उन्होंने उद्योग को बढ़ाया तो वह 35 या 36 प्रतिशत ही कृषि में रह गए। दूसरी ओर चीन ने कृषि की ओर ध्यान दिया। चीन में भुखमरी की हालत नहीं हुई। आज हिन्दुस्तान की भी हालत भुखमरी की नहीं है, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं खाद्यान्न के लिए, हम हाथ फैलाते हैं अपनी शान-ओ-शौकत के लिए। सरकार को इन बातों को समझना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य 8.7 रखा गया था, जो आज 8.5 प्रतिशत ही पूरा हो सका क्योंकि हमारी गिरावट हुई और इस गिरावट के लिए निश्चय ही मैं समझता हूं कि सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा समय से रहा हूं, आप

यह न समझें कि आपका बहुत समय ले रहा हूं, महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन इसलिए मैं आपका समय ले रहा हूं कि आप इतने विभागों का, इतने मंत्रालयों का और इतनी बड़ी राशि का एप्रोप्रिएशन बिल हमारे सामने ले आए हैं लेकिन उस पर आपने चर्चा तो की नहीं, केवल श्रम मंत्रालय की चर्चा की। आपने स्वयं इसको देखा है कि इसमें किस तरह का विरोधाभास है। एप्रोप्रिएशन बिल में किस तरह का विरोधाभास है, एक-दो बातों की ओर देखें तो आपको लगेगा और इसलिए मैं विरोधाभास की बात कह रहा हूं कि आपको इसमें भी संतुलन पैदा करना है। बहुत मोटी चीज मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं। लोक सभा और राज्य सभा दोनों जनतंत्र के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसी संसद भवन के अंदर हम भी इस गुम्बज के नीचे बैठे हैं और इसी संसद भवन में दूसरी गुम्बज के नीचे हमारे भाई भी बैठे हैं। ठीक है, उनकी संख्या अधिक है, लोक सभा के लिए आपने खर्च की मांग की है 20 करोड़ 36 लाख रुपए की और राज्य सभा के लिए 9 करोड़ 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति भवन बहुत बड़ी चीज है, मैं मानता हूं कि इसमें हमारी शान-ओ-शौकत है और राष्ट्रपति हमारी मर्यादा है, सब कुछ है, लेकिन आप देखिए कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन के रख-रखाव के लिए आपने 3 करोड़ 15 लाख रुपए का प्रावधान रखा है और उप राष्ट्रपति, जो हमारे भी चेयरमैन हैं, उनके लिए केवल 17 लाख रुपए का, करोड़ रुपए भी नहीं। 10वां 20वां हिस्सा आपने रखा है। इन सारी चीजों को मैंने देखा इसलिए मैंने जान-बूझकर आपके साथ कुछ कहने की कोशिश की है। पुलिस में आप कितना खर्च कर रहे हैं 17 अरब, 72 करोड़ 96 लाख रुपए, क्योंकि विधि-व्यवस्था की देख-रेख आपको करनी है, उसके लिए आप सक्षमता रख रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन विधि-व्यवस्था की वहीं रख-रखाव होती है, जहां विधि-व्यवस्था खराब हो। जहां देश में सुरक्षा की कमी हो, वहां आप इतना खर्च कर रहे हैं, दूसरी ओर ऐजुकेशन या साक्षरता, जो सबसे बड़ा प्रश्न है—हम अगर आज साक्षर हो जाए तो हमारी जनसंख्या कम होगी, हम दूसरे कामों में मदद मिलेगी, तो पुलिस के ऊपर हम रख रहे हैं 17 अरब और पूरे देश में शिक्षा के ऊपर हमने रखा है 18 अरब एक करोड़ रुपया। यानी कि पुलिस के डंडे और शिक्षा और शोध कार्य और पुस्तकों और बच्चों को, इन दोनों को हमने लगभग बराबर कर दिया है।

इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इसे हम रस्म अदायगी के तौर पर पास भले ही करलें लेकिन देश की जनता कभी भी अपने दिल से इसको पास नहीं कर सकती है और इसलिए पास नहीं कर सकती है कि आपने इस पर संतुलन नहीं रखा ... (व्यवधान) मैं समाप्त कर रहा हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You cannot mention the President and the Chairman. (*Interruptions*) This is not proper. You tried to compare. That should not be there. comparision are avoidable and should be avoided.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: I have not made any point at all, Sir. Only I have mentioned that here is the figure. I have only showed the figure.

इसलिए उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं वह यह कि देश की समस्याओं को अपने सामने रखें। आप अवमूल्यन पर ध्यान दें, मूल्यवृद्धि पर ध्यान दें, आप भ्रष्टाचार की ओर ध्यान दें, जो महंगाई बढ़ रही है आप उसकी ओर ध्यान दें और विदेशी कर्ज लेकर जो शान-शौकत, आलीशान मकान और बड़े-बड़े जो अभियान हम चला रहे हैं, मिनिस्टर्स के बंगले सजा रहे हैं, रेड कारपेट बिछा रहे हैं, गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, आपको इनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तब इस गरीब देश के प्रति आप सही रूप में न्याय कर सकेंगे, नहीं तो मैं समझूंगा कि सरकार न्याय के ऊपर नहीं अन्याय के उपर खड़ी है।

[श्री शंकर दयाल सिंह]

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं यह आशा करता हूं कि जिस बड़े वेग के साथ हमारे नए वित्त मंत्री आये थे, जिनका मैं प्रशंसक था कि कम से कम उन्होंने देश में जो बुरी सारी बातें हो रही थीं, उससे लोगों का ध्यान हटाकर आर्थिक मुद्दे की ओर लाकर खड़ा किया । इसलिए उनसे भी यह कहना चाहता हूं कि इसको गंभीरता से देखें और देखते हुए इन समस्याओं का निदान करें, जिससे सही मायनों में हम कल स्वर्णकाल की कल्पना कर सकें ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): At six o'clock there is a statement to be made by the Minister of External Affairs.

Now, Mr. Ashis Sen. You can continue up to six. Thereafter we will have the statement. And then if you have not finished you can continue tomorrow.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu and Kashmir): What about the clarifications?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Clarifications we will take up tomorrow. If possible, today itself we will finish it.

SHRI ASHIS SEN (West Bengal): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir.

Now, this is an Appropriation Bill which is a follow-up of the Budget proposals. But do these proposals indicate a state of good health of our economy or are the measures taken going to remedy or treat the illness we are suffering from? The amount has to be appropriated from the Consolidated Fund of India for services. Services to which section of the society, which portion, which class of our people, for which the amount is to be drawn? Let us look around the country. Let us look at Tripura, let us have a glimpse of Kashmir, the Punjab, then in general, and let us look at the situation happening in Bihar, Andhra Prasad, as far as the weaker sections of the people are concerned.

SHRIMATI KAMLA SINHA (Bihar): Maharashtra.

SHRI ASHIS SEN: Maharashtra. Thank you, Madam. Are we taking care of these things or simply presenting an Appropriation Bill?

Now, what is the position of our internal debt? In 1990-91 it was to the extent of Rs. 279,528 crores. It is the reported estimate. And today according to the Economic Times report this morning, the external debt is now to the tune of 70 billion dollars which works out to be Rs. 182,000 crores. Now, another tranche of six billion dollars or Rs 15,000 crores from the IMF is on the tap. It is reported that the Finance Minister has stated this in the *Washington Post*. In this process, our gross debt comes to the extent of Rs. 4,61,000 crores and the interest we have paid in 1990-91 is about Rs. 22000 crores. That shows how much amount of the revenue goes by way of interest alone. Mr. Shankar Dayal Singh, a little while ago, was talking about how much allocation has been made for the people in the rural areas, for water resources as compared to the administrative expenses for police. I am only drawing attention to what Mr. Shankar Dayal Singh told a little earlier. Now if in this way we have to increase our indebtedness domestic as well as foreign, how much interest we have to pay and in that manner how much fund will be remaining for us, for our developmental work or to meet the minimum needs of our country? How to meet the situation? That is a big question. Should it be proper on our part to reduce the subsidy on food and fertilizer? If we reduce the subsidy—that we have discussed earlier in this House—then who are affected? It is the poorer section and the Kisans. Now what I feel is that

if we want to reduce the gap in the receipts and the expenditure what is needed essentially is a political will. Do we have a political will to reduce it? In that case the whole budget structure and the idea of appropriating amounts from the Consolidated Fund of India would have taken completely a different picture, not the way it has been presented today. Why is the Government not willing to do that? Because this requires touching the monopolists, big business and perhaps they cannot overlook the pressure from abroad also. That is why the lending institutions from abroad are interested in these things to be done. Does it indicate the good health of our economy and the managers of that economy? That is my plain question which I put to the Finance Minister or his deputy who is present here. The export subsidy, if I am correct, is to the tune of Rs. 1650 crores and more but receipts do not come back. Mr. Yashwant Sinha, as the Finance Minister was on record saying that our outstanding export receipts are to the tune of one billion i.e. 26000 crores of rupees. Exports were made but the proceeds were not repatriated to our country. Have we taken note of it? We have got an institution, the Reserve ank of India. Is it playing a proper role for that? Then whatever exports are processed through the Reserve Bank of India and Customs, do we take care to see that the amount that is lying outstanding is coming back from abroad on account of the exports made? Why do you give subsidies to the exporters? A Bill is coming about this to introduce foreign currency bonds. In this way this money which is not being repatriated out of the gain from the exports will come in the nature of deposits from a non-resident Indian who will pass on that money to India and that will be allowed to be a normal tax-free deposit in the assets of the particular individual. This will be coming in crores. That is why I have mentioned about it. That Bill perhaps is coming up tomorrow.

To raise the Central funds, is it necessary that the States' allotments or the States' claims should be curtailed?

The Centre should help the States more rather than go on curtailing the allocation. What has happened is, there is replacement of cess by royalty. Who has been affected? States like Bihar, Assam, Madhya Pradesh, West Bengal have been affected because of this change from cess to royalty. Is there any manoeuvrability for those States to have more revenue out of those resources that are available under the ground there? No, that has been curtailed. More than that what we need for the Centre to understand is that if the States become weaker financially, if they are not in a position to develop, I draw the attention to what Shri Shankar Dayal Singh said a little earlier that if the capital is to build up as a big edifice and the ground around is not there, will the edifice remain?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Sen, you will please continue tomorrow.

6.00 P. M.

STATEMENT BY MINISTER

Recognition by the Government to the three Baltic States of Estonia, Latvia and Lithuania

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI EDUARDO FALEIRO): Sir, Honourable Members will recall that the New Union Treaty of USSR that was intended to be signed on the 20th August, 1991, had envisaged that the constituent Republics of USSR would sovereign States. The New Treaty could not be signed due to the attempted coup in that country on the 19th August, 1991.

On the 6th September 1991, the USSR State Council, the highest